डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 16 मार्च, 2025, डिस्पेच दिनांक 16 मार्च, 2025

| वर्ष 68 | अंक 20 | भोपाल | 16 मार्च, 2025 | पृष्ठ 08 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

किसानों को अब पांच रुपये में मिलेगा बिजली का स्थाई कनेक्शन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

तीन साल में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे

किसानों द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली नगद खरीदी जाएगी

किसानों की आय बढ़ाने और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी

प्रधानमंत्री श्री मोदी के किसानों के प्रति प्रेमभाव का प्रकटीकरण है उनकी कल्याणकारी योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कृषकों से फसल चक्र में बदलाव का किया आव्हान

मध्यप्रदेश जैविक खेती में अपनी विशेष पहचान करें स्थापित

जिला स्तर पर लगेंगे विभिन्न कृषि मेले

मुख्यमंत्री ने कृषकों को खेती को बेहतर बनाने, नवीन तकनीक अपनाने और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने का दिलाया संकल्प

किसान हितैषी नीतियों-निर्णयों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आभार जताने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे किसान

गेहूँ का समर्थन का मूल्य 2600 रुपये करने और धान उपार्जन पर 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि से प्रसन्न हैं किसान

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को अब 5 रुपये में बिजली का स्थाई कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य क्षेत्र को यह व्यवस्था तत्काल आरंभ करने के निर्देश देते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह किसानों की सरकार है। उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए हर संभव कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार सोलर पंप के माध्यम से किसानों को बिजली उत्पादन में भी आत्म-निर्भर बनाएगी। अगले तीन वर्ष में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर, किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाएगी। प्रतिवर्ष 10-10 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही किसानों द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली खरीद कर उन्हें नगद भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसान आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री निवास पहुंचे किसानों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सदैव किसानों के साथ है और उनके हित में निरंतर कार्य कर रही है। हम 2 हजार 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद रहे हैं, इसमें 175 रुपये बोनस राशि है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2003-04 में प्रदेश में गेहूँ खरीदी का सरकारी दाम मात्र 447 रुपए था जो राज्य सरकार ने बढ़ा कर 2 हजार 600 प्रति क्विंटल किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार वर्ष 2024 के लिये धान उपार्जन पर 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सोलर पंप के माध्यम से किसानों को स्थाई कनेक्शन भी दिए जाएंगे। हाल ही में अस्थाई कनेक्शन वाले डेढ़ लाख किसानों को स्थाई कनेक्शन दिलवाए गए हैं और इसकी राशि भी कम की गई है। तीन हॉर्स पॉवर वालों को सोलर पंप की 5% राशि, 5 से 7.50 हॉर्स पॉवर के लिए 10% राशि देना होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार का किसानों के प्रति प्रेम है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हर गरीब, जरूरतमंद के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की है। दो लाख करोड़ रुपए के व्यय से 100 करोड़ से अधिक लोगों को वर्ष 2028 तक अन्न देने की व्यवस्था की गई है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रत्येक गरीब का जीवन बेहतर बनाने के भाव का प्रकटीकरण और राम राज्य की अवधारणा को साकार करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री मोदी किसानों को उनका हक दिला रहे हैं। यह हमारी सरकार की उदात्त भावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषकों से फसल चक्र में बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धान के बदले में मूंगफली और प्राकृतिक फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जैविक खेती से मध्यप्रदेश अपनी अलग पहचान स्थापित करें। उन्होंने कहा कि जीआईएस भोपाल में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश में उत्पादित कपास से क्रांति आने वाली है। किसान परिवार के व्यक्ति को रोजगार देने वाली टेक्सटाइल मिलों को 5 हजार रुपये का बोनस दिया जाएगा। कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। गेहूँ और धान पर दिए जा रहे प्रोत्साहन के समान ही दुग्ध उत्पादन पर भी प्रोत्साहन स्वरूप बोनस प्रदान किया जाएगा। दस से अधिक गाय पालने वालों को अनुदान दिया जाएगा। गांव-गांव में गोपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। गौ-शाला चलाने वालों को प्रति गाय 20 रुपये के स्थान पर 40 रुपये का अनुदान देकर गौ-शालाओं को सक्षम बनाया जाएगा। गौ-माता परमात्मा की हम पर असीम कृपा है। गौ-माता प्रकृति और परमात्मा के बीच संबंध का सूत्र है। बेसहारा, अशक्त और वृद्ध गौ-माताओं के आश्रय के लिए भोपाल सहित सभी बड़ी नगर निगमों में 10 हजार क्षमता की गौ-शालाएं बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आने वाले समय में उन्नत कृषि यंत्र, उन्नत बीज और कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तर पर कृषि मेले लगाए जाएंगे। वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार वैश्विक स्तर पर उपलब्ध श्रेष्ठतम बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत एक लाख करोड़ की केन-बेतवा लिंक परियोजना और 70 हजार करोड़ से चंबल-काली सिंध-पार्वती लिंक परियोजना का क्रियान्वयन जारी है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के सहयोग से ताप्ती नदी पर तीसरी नदी जोड़ो परियोजना आरंभ होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सर्वाधिक महत्व कृषकों को दिया है। कृषक अन्नदाता ही नहीं, अपितु जीवन दाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण भारत के विकास को गति प्रदान की। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत को समझना है तो गांव को समझना होगा। भारत में विकास को गति देने के लिए किसानों के जीवन को समृद्ध और सशक्त बनाना होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए ही किसान, गरीब, महिला और युवा पर ध्यान केंद्रित किया है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मंत्री श्री सारंग ने की जीआईएस में सहकारिता विभाग की फॉलो-अप समीक्षा

सीपीपीपी के जरिये निवेश करने वालों के लिये निवेश विंग में नोडल अधिकारी करें नियुक्त

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सहकारिता विभाग में निवेश विंग की स्थापना के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने विंध्याचल भवन स्थित सहकारिता विभाग में सहकारिता संबंधी निवेशकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा। साथ ही उन्होंने एक कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिये, जो आये प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद हायर लेवल पर प्रस्तुत करेगी। मंत्री श्री सारंग मंत्रालय में जीआईएस के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे।

हितग्राहियों को परस्पर लाभ देने के लिये सीपीपीपी मॉडल

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि विभाग के को-ऑपरेटिव पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के हितग्राहियों को परस्पर लाभ प्रदान करने के साथ ही प्रदेश के दूसरे और तीसरे दर्जे के क्षेत्रों के विकास को तिगुनी गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इसीलिये निवेशकों का विशेष ख्याल रखा जाये। सिंगल विण्डो सिस्टम से किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण हो।

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल के अंतर्गत कुल अनुमानित 2305 करोड़ रुपये के 19 एमओयू हुए हैं। इनमें प्रमुख रिलायंस द्वारा 1000 करोड़ और वैधनाथ ग्रुप द्वारा निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैजेस्टिक बासमती राइस प्राइवेट लिमिटेड रायसेन द्वारा 1000 करोड़ रुपये, आरएम ग्रुप द्वारा 100 करोड़ रुपये, मशरूम वर्ल्ड भोपाल द्वारा 100 करोड़ रुपये, वी विन लिमिटेड भोपाल द्वारा 40 करोड़ रुपये, न्यूट्रेलिस कृषि उत्पादक सहकारी समिति नोएडा यूपी द्वारा 30 करोड़ रुपये, एग्रीविस्टा एआई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 25 करोड़ रुपये और सवीर बॉयो टेक लिमिटेड नोएडा यूपी द्वारा 10 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही प्रतिभा सिंटेक्स इंदौर, पतंजलि, भारतीय बीज सहकारी समिति, न्यूट्रेलिस कृषि उत्पादक सहकारी समिति नोएडा आदि ने भी मध्यप्रदेश में निवेश में रुचि जाहिर की है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री आलोक कुमार सिंह, सहकारिता आयुक्त श्री मनोज पुष्प, अपेक्स बैंक के प्रभारी प्रबंध संचालक श्री मनोज कुमार गुप्ता, राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, बीज संघ के प्रबंध संचालक श्री महेन्द्र दीक्षित सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गेहूँ उपार्जन के लिये 31 मार्च तक होगा पंजीयन : खाद्य मंत्री श्री राजपूत

समर्थन मूल्य पर गेहूँ की बिक्री के लिए 5 लाख 17 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन

भोपाल : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 5 लाख 17 हजार 632 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। मंत्री श्री राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि गेहूँ की बिक्री के लिए समय-सीमा में पंजीयन जरूर करायें। उन्होंने बताया है कि गेहूँ की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में 15 मार्च से 5 मई तक होगी। गेहूँ की खरीदी 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जायेगी। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और 175 रूपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा बोनस दिया जा रहा है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की बिक्री के लिए जिला बुरहानपुर में 31, खरगौन में 1616, बड़वानी में 99, अलीराजपुर में 46, खंडवा में 6079, धार में 15,940, झाबुआ में 2850, इंदौर में 27,075, मंदसौर 11,275, नीमच 3768, आगर-मालवा में 14,469, देवास में 26,904, रतलाम में 12,908, शाजापुर में 35,346, उज्जैन में 56,805, अशोकनगर में 1276, शिवपुरी में 1670, ग्वालियर में 1612, दतिया में 2288, गुना में 2199, भिंड में 2266, श्योपुर में 3260, मुरैना में 1025, जबलपुर 1471, बालाघाट 112, कटनी में 2093, पांढुर्णा 19, डिंडौरी में 658, छिंदवाड़ा में 3054, सिवनी में 8530, नरसिंहपुर में 6286, मंडला में 4598, हरदा में 1610, बैतूल में 3413, नर्मदापुरम में 27,222, विदिशा में 30,556, रायसेन में 31,197, राजगढ़ में 31,171, भोपाल में 17,182, सीहोर में 59,141, सतना में 2811, रीवा में 1894, सिंगरौली में 369, मऊगंज 94, मैहर में 924, सीधी में 1382, अनूपपुर में 103, उमरिया में 1447, शहडोल में 2246, पन्ना में 2416, निवाड़ी में 431, दमोह में 7636, टीकमगढ़ में 2705, छतरपुर में 3676 और सागर में 20,378 किसानों ने पंजीयन कराया है।

दुग्ध सहकारी समितियों के नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन

उज्जैन। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, नई दिल्ली, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल एवं सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में उज्जैन जिले की दुग्ध सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं संचालक सदस्यों के लिए आयोजित तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध सहकारी समितियों को सशक्त नेतृत्व प्रदान करना एवं उनकी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाना था।

नवाचार एवं नेतृत्व कौशल पर जोर

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त श्री के. पाटनकरएवंविशेष अतिथि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, दुग्ध सहकारी संघ, उज्जैन श्री डी. के. पाण्डेने सहभागियों को संबोधित किया। श्री पाटनकर ने अपने संबोधन में कहा किसशक्त नेतृत्व से ही सहकारी समितियां नवाचार की ओर बढ़ सकती हैंऔर दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ अन्य दुग्ध उत्पादों के निर्माण पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारी समितियों को अपनी व्यवसायिक रणनीति में नए तकनीकों को अपनाना चाहिए, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो। श्री डी. के. पाण्डे नेदूध की गुणवत्ता सुधारने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से समितियों की कार्यप्रणाली में बेहतरी लानेके विषय पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता सुधार से न केवल दूध की मांग में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि संभव हो सकेगी।

दुग्ध संघ के प्रतिनिधि श्री एस. के. सोनीने "सहकार से समृद्धि" विषय पर चर्चा की और सहकारी समितियों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यदि सहकारी समितियां संगठित रूप से कार्य करें और तकनीकी नवाचार अपनाएं, तो वे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकती हैं।

श्री संजीव शर्मा ने अमूल का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि सहकारी समितियों की सही कार्यप्रणाली कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकती है। उन्होंने कहा कि "अमूल एक सफल सहकारी मॉडल है, जिसे यदि हम अपनाएं तो हमारे दुग्ध उत्पादक किसानों को भी व्यापक लाभ मिल सकता है।"

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर के प्राचार्यश्री दिलीप मरमट ने सहकारिता के इतिहास, सिद्धांत एवं पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ सहकारी समितियां ही किसानों की आर्थिक उन्नति का आधार बन सकती हैं।उन्होंने सहकारी समितियों को संगठित रूप से कार्य करने की सलाह दी, जिससे वे बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम मेंउज्जैन, रतलाम और शाजापुर जिलों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षार्थियों

को दुग्ध व्यवसाय, वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट प्रक्रिया, विपणन रणनीति एवं नेतृत्व कौशल पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। समापन अवसर पर सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए एवं उनके योगदान की सराहना की गई। प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण को अत्यंत लाभदायक बताया और कहा कि इससे उन्हें अपने व्यवसाय को नई दिशा देने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर उज्जैन जिला सहकारी संघ सेश्री सुमेर सिंह सोलंकी, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर से प्रशिक्षकश्री प्रदीप कुमार रैकवार, श्री राहुल श्रीवास एवं श्री सुयश शर्मा उपस्थित रहे। तीन दिवसीय यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दुग्ध सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं संचालक सदस्यों को नेतृत्व कौशल विकसित करने एवं सहकारी क्षेत्र में नए अवसरों को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में "डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला" का उद्घाटन किया

ग्रामीण पलायन की समस्या का समाधान करने के साथ छोटे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए डेयरी एक महत्वपूर्ण विकल्प है

मोदी सरकार सहकार से शक्ति, सहयोग और समृद्धि के तीन सूत्रों के साथ-साथ profit for people के मंत्र चरितार्थ कर रही है

वर्तमान समय में फार्म से फैक्ट्री तक की सम्पूर्ण चैन गाँव में ही स्थापित किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए

गुजरात में माइक्रो ATM के मॉडल से प्रदेश के पशुपालकों को अभूतपूर्व लाभ मिल रहा है, इस मॉडल को नाबार्ड देश के हर जिले तक पहुंचाए

सीमांत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए गाँव से ग्लोबल तक की यात्रा, समूह से सफलता तक का विश्वास और फार्म से फैक्ट्री तक की पूरी श्रृंखला विकसित करना जरूरी

श्वेत क्रांति 2.0 के तहत हर राज्य व UT में एक राज्यस्तरीय संघ और देश के 80% जिलों में दुग्ध संघ बनाने का लक्ष्य हो

श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्ष्य सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी है

नई दिल्ली | केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में "डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला" का उद्घाटन किया। डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी, कुशलता और संसाधनों की सर्कुलरिटी से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' का विजन साकार होगा।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज जब हम श्वेत क्रांति-2 की तरफ बढ़ रहे हैं तब सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति-1 से अब तक जो हमने हासिल किया है उससे सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी को पूरा करना अभी बाकी है। श्री शाह ने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्ष्य सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी है और श्वेत क्रांति-2 की शुरूआत से ही इनका ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत का डेयरी क्षेत्र देश के साथ-साथ ग्रामीण विकास और भूमिहीन और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की पोषण की चिंता करता है, देश को दुनिया का नंबर एक दूध उत्पादक बनाने में योगदान देता है और कृषि के अलावा किसानों को अतिरिक्त आय भी प्रदान करता है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे सामने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था, दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र और 2047 में पूर्ण विकसित देश बनाने के तीन लक्ष्य रखे हैं। इन तीनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए हमें हर क्षेत्र में संभावनाओं का शत-प्रतिशत दोहन करने की पद्धति विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर ने आज सर्कुलरिटी के संबंध में गुड प्रैक्टिसिस को 250 दूध उत्पादक संघों तक पहुंचाने की विज़नरी शुरूआत की है।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत की कृषि प्रणाली छोटे किसानों पर आधारित है और गांवों से शहर की ओर हो रहा पलायन छोटे किसानों की समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पलायन की समस्या का समाधान करने के साथ छोटे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए डेयरी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। श्री शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र की सभी संभावनाओं को शत-प्रतिशत एक्सप्लोर करने के लिए होलिस्चिक अप्रोच के साथ काम करने के लिए यह सेमिनार बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 साल में देश में खेती में खुशहाली की एक अच्छी शुरूआत हुई है। उन्होंने कहा कि गांव से ग्लोबल तक जाने का हौंसला भी बढ़ा है और पद्धतियां भी बनी हैं और कोऑपरेटिव के माध्यम से समूह से सफलता पाने का विश्वास भी बढ़ रहा है। श्री शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि फार्म से फैक्ट्री तक की पूरी चेन ग्रामीण क्षेत्र में ही हो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सहकार से शक्ति, सहकार से सहयोग और सहकार से समृद्धि के तीन सूत्रों के साथ-साथ profit for people के मंत्र चरितार्थ कर रही है।

श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ-साथ people first भी है। उन्होंने कहा कि profit for people के सूत्र को हम सहकारिता के माध्यम से ही चरितार्थ कर सकते हैं। आज यहां डेयरी क्षेत्र में सर्कुलरिटी पर मार्गदर्शिका का विमोचन, छोटी और बड़ी बायोगैस कम्प्रेस्ड परियाजनाओं की वित्तीय सहायताओं के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की योजनाओं और NDDB और Sustain Plus परियोजना का शुभारंभ भी हुआ है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जैविक खाद का शत-प्रतिशत दोहन करने के लिए ज़िला स्तर के दुग्ध संघों और ग्रामीण डेयरियों को उन किसानों को भी सहकारिता के नेट में लाना होगा जो अभी कोऑपरेटिव से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि कई किसान प्राइवेट डेयरी को दूध देते हैं, लेकिन उनके गोबर का प्रबंधन सहकारिता क्षेत्र को करना चाहिए, जिससे हमारी मिनिमम वायबिलिटी की समस्या दूर होगी और प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहे किसान को सहकारिता क्षेत्र की ओर आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। श्री शाह ने कहा कि गैस उत्पादन के क्षेत्र के सफल प्रयोगों को 2 साल के लक्ष्य साथ 250 जिला दुग्ध उत्पादक संघों में मॉडल के रूप में सफलतापूर्वक लागू करने का कार्यक्रम बनाना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमने सारे खाते कोऑपरेटिव बैंकों में खोलने के लिए भी Cooperation Amongst Cooperatives की शुरूआत की है और आज गुजरात में 93 प्रतिशत संस्थाओं के खाते सहकारी बैंकों में खुले हुए हैं। इससे सहकारिता के लिए अपने आप धन भी उपलब्ध हुआ है और बैंक भी मज़बूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में माइक्रो ATM के मॉडल से प्रदेश के पशुपालकों को अभूतपूर्व लाभ मिल रहा है, इस मॉडल को नाबार्ड देश के हर जिले तक पहुंचाए। श्री शाह ने कहा कि हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि फैट नापने से लेकर डेयरी के सभी प्रॉडक्ट्स के साथ जुड़ी सभी मशीनों का उत्पादन भारत में हो। उन्होंने कहा कि कार्बन क्रेडिट को हमारी पद्धति का हिस्सा बनाना चाहिए और इसका फायदा किसान को मिले इसके लिए कोऑपरेटिव मॉडल पर वैज्ञानिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज देश में 23 राज्यस्तरीय संघ हैं लेकिन हमें श्वेत क्रांति 2.0 के तहत हर राज्य व UT में एक राज्यस्तरीय संघ और देश के 80% जिलों में दुग्ध संघ बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान की 28 विपणन डेयरियों की संख्या बढ़ाकर 3 गुना कर सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव डेयरी क्षेत्र में उपभोक्ता के पास से आने वाले पैसे में से 75 प्रतिशत से अधिक किसानों को वापस मिलता है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किसानों को 32 प्रतिशत पैसा वापस मिलता है। उन्होंने कहा कि हमें देश के हर किसान के लिए इस अंतर को कम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके साथ ही, 16 करोड़ टन गोबर को हमारे कोऑपरेटिव के नेट में लाने का भी प्रयास करना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि मीथेन और कार्बनडाइऑक्साइड के उत्सर्जन में बहुत कमी आई है और इसका सौ प्रतिशत कार्बन क्रेडिट किसानों के बैंक खाते में जाना चाहिए और यही सर्कुलरिटी का असली मतलब है। उन्होंने कहा कि डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर महिलाओं को रोजगार देने के मामले में भी बहुत काम करता है और आज कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर में 72 प्रतिशत महिलाएं काम कर रही है। श्री शाह ने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर में माताओं बहनों के रोजगार और उनके सशक्तिकरण पर काम होता है।

कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, प्रोफेसर एस. पी. सिंह बघेल एवं श्री जॉर्ज कुरियन, श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने "कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि", पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित

देशभर के कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े एक्सपर्ट के मिले सुझावों से बजट प्रस्तावों का क्रियान्वयन किया जाएगा

कृषि विकास और किसानों की समृद्धि के बिना विकसित भारत का निर्माण नहीं हो सकता - श्री शिवराज सिंह

कृषि क्षेत्र का विकास और गांवों की समृद्धि सरकार का लक्ष्य - श्री शिवराज सिंह

मखाना बोर्ड के गठन के लिए मिले सुझावों पर काम करेंगे-केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान

बजट के प्रस्तावों को जमीन पर उतारना हमारा संकल्प-श्री शिवराज सिंह

वेबीनार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिलना किसानों और एक्सपर्ट के लिए सौभाग्य

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र और किसान भाई-बहन समृद्ध और संपन्न बन रहे – श्री शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने "कृषि और ग्रामीण समृद्धि" पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार में श्री शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित केन्द्रीय कैबिनेट और राज्यमंत्रियों से नीतियों में निरंतरता, विकसित भारत विज़न, बजट को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने, कृषि विकास, दलहन उत्पादन और उन्नत बीज सहित कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए हमारी छह सूत्रीय रणनीति है। पहला उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन का ठीक दाम, चौथा नुकसान की भरपाई, पांचवा कृषि का विविधिकरण और छंटवां प्राकृतिक खेती।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं, जहां किसान समृद्ध और सशक्त बनें। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए लक्ष्य तय है, उसको तेज़ी से जमीन पर उतारकर हमें जल्द परिणाम देना है। देश में अनाज, फल, सब्जियों और दूध का उत्पादन बढ़ा है। सब्जी और फलों की प्रोसेसिंग और बढ़ाना है। भारत केवल अपने लिए अन्न, फल सब्जी ना उगाए, बल्कि दुनिया का फूड बास्केट बन जाए, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारतीय कृषि को वैश्विक महाशक्ति में बदलने के लिए समर्पित है। विकसित भारत 2047 का उद्देश्य, आत्मनिर्भरता, सतत विकास और किसानों की आय बढ़ाना है। श्री चौहान ने कहा कि हम जो भी नीतियां बनाते हैं, वो किसानों को सशक्त बनाने, उनकी आय बढ़ाने और कृषि के आधुनिकीकरण करने के लिए होती है। केन्द्र सरकार, किसानों के कल्याण, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य आधुनिक तकनीक और सतत प्रथाओं को अपनाते हुए भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।

श्री चौहान ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मिलकर बजट के सभी प्रस्तावों को नीचे जमीन तक उतारना है। उन्होंने कहा कि इस वेबिनार में जिस गहराई और गंभीरता से विचार किया है, वो बजट में आए प्रस्तावों को जमीन तक उतारने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। कई विचार ऐसे भी आए हैं, जो सीधे बजट से सबंधित नहीं है, लेकिन एलाइट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और एलाइट सेक्टर कृषि, किसान और ग्रामीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जो वेबिनार में अपनी बात नहीं रख पाए हैं, वो लिखित सुझाव जरूर भेंजे, लिखित सुझावों पर शीघ्रता से विचार कर उन्हें कैसे लागू करें, उस पर काम करेंगे। लिखित सुझावों को और बजट के प्रस्तावों को नीचे जमीन तक लागू करने के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास और इससे जुड़े विभागों के मंत्रियों और सचिवों को चार महीने में एक बार बैठक जरूर करनी चाहिए।

कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि पर आयोजित वेबीनार में आज मखाना बोर्ड के गठन को लेकर भी विशेषज्ञों के सुझाव आए। मखाना बोर्ड के संबंध में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वेबीनार में आए सुझावों को कैसे जमीन पर लागू करें इसे लेकर भी आगे काम करेंगे। वही श्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना बोर्ड के गठन को लेकर आए सुझावों के लिए मंत्रियों और विशेषज्ञों को धन्यवाद दिया

दुग्ध सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

धार | मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल एवं जिला सहकारी संघ धार के संयुक्त तत्वावधान में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल के सदस्यों हेतु दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमका सफल आयोजनदिनांक 27 एवं 28 फरवरी 2025को मनावर तहसील में किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दुग्ध सहकारी संघ बड़वानीकी क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमती कुंता चौहान एवंधार दुग्ध सहकारी संघ के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री वास्केल विशेष रूप से उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण में दिए गए महत्वपूर्ण विषय

कार्यक्रम में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के पूर्व प्राचार्य श्री के. एल. राठौर ने

सहकारी संस्थाओं की प्रबंधन व्यवस्था, सहकारिता के सैद्धांतिक पहलू, संस्थाओं में बैठकों का महत्व, बैठक बुलाने की प्रक्रिया एवं आवश्यक तैयारियों पर विस्तृत जानकारी दी।

इसी क्रम में इंदौर दुग्ध सहकारी संघ के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एन.के. पगारे ने आदर्श दुग्ध सहकारी समितियों के गठन, दुग्ध उत्पादन वृद्धि, दुधारू पशुओं के उचित रखरखाव आदि विषयों पर प्रशिक्षार्थियों का मार्गदर्शन किया।

जिला सहकारी संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारीश्री शुभेंद्र सिंह पंवार ने प्रशिक्षण की भूमिका एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की। समापन समारोह में प्रशिक्षार्थियों को प्रशस्ति पत्र, पेन, पौधे, बुकलेट एवं लैपटॉप बैग वितरित किए गए। इस प्रशिक्षण में 40 से अधिक दुग्ध सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन श्री शुभेंद्र सिंह पंवार ने किया एवं आभार प्रदर्शन श्री लक्ष्मीनारायण चावड़ा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षक श्री राहुल श्रीवास ने भी सहकारिता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दुग्ध सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण एवं कुशल संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना में धान पर 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा अतिरिक्त लाभ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

गेहूँ पर 175 रूपये प्रति क्विंटल मिलेगा बोनस

बालाघाट के खिलाड़ियों को मिली हॉकी एस्ट्रो टर्फ की सौगात

5 वर्षों में 2 लाख 70 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरियां

एक लाख सरकार पदों पर भर्ती जारी

नक्सलवाद के पैर नहीं जमने देंगे

सभी योजनाएं चालू रहेंगी

मुख्यमंत्री ने बालाघाट में 326 करोड़ 60 लाख रूपये के 117 विकास कार्यों का किया भूमि-पूजन और लोकार्पण

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट के किसान सम्मेलन में किसानों को अभूतपूर्व सौगात देते हुए कहा कि अब प्रदेश में धान उत्पादक किसानों को 4 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गेहूँ उत्पादक किसानों को भी प्रति क्विंटल 175 रूपये अतिरिक्त बोनस राशि दी जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मूल्य संवर्धन योजना (प्राइस सपोर्ट स्कीम) अंतर्गत वर्ष 2024 में 6.69 लाख किसानों द्वारा 12.2 लाख हेक्टेयर रकबे में उत्पादित धान का विक्रय किया गया है। धान उत्पादक किसानों को मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना में प्रति हेक्टेयर 4000 रूपये का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश के किसानों को 488 करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गेहूँ उत्पादक किसानों को भी समर्थन मूल्य 2425 रूपये के अतिरिक्त 175 रूपये प्रति क्विंटल की बोनस राशि दी जायेगी। इस प्रकार गेहूँ के उपार्जन पर प्रति क्विंटल 2600 रूपये की राशि मिलेगी। इस वर्ष प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन अनुमानित है। प्रदेश के किसानों को 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में मिलने से लगभग 1400 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि का लाभ होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जा रही है। आने वाले 5 वर्षों में 2 लाख 70 हजार पदों पर विभिन्न सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारी सरकार वर्ष 2028 तक सरकार 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रदेश में चल रही योजनाएं यथावत चलती रहेगी। कोई भी योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार नंबर वन पर बना रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान सम्मेलन में सभी को विकास का संकल्प भी दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने 1412 दिव्यांगजनों और 1040 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित करने के साथ अन्य विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है और अब हम चौथे नंबर पर आने के लिए अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश भारत है, और यह प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान में सर्वाधिक जीएसडीपी ग्रोथ रेट 13 प्रतिशत मध्यप्रदेश की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्थानीय कलेक्टर को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पक्के मकान के बगैर नहीं रहेगा।

कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

उज्जैन: मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित, उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना था।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन जिला सहकारी संघ उज्जैन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सहकारी नेता संजय कौशल द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर जिला सहकारी संघ उज्जैन के प्रभारी प्रबंधक सुमेरसिंह सोलंकी ने स्वागत भाषण दिया।

कार्यक्रम में सहकारी क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, इंदौर के सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य एवं सहकारिता अधिकारी निर्दोष दिलीप असरामनी, उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष राम साहबला, एवं जिला सहकारी संघ के सचिव शिवकुमार शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

मुख्य बिंदु और प्रशिक्षण के प्रमुख विषय

1. **ऋण पात्रता का नया मानक:**
   - संजय कौशल ने बताया कि एक नए डेटा सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति डिफॉल्टर है, तो उसे ऋण लेने की पात्रता नहीं होगी।
   - इससे सहकारी संस्थाओं को वित्तीय जोखिम से बचाने में मदद मिलेगी और ऋण वसूली की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
2. **सहकारी संस्थाओं की मजबूती और नेतृत्व विकास:**
   - प्रशिक्षण में सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष, संचालक, समिति प्रबंधकों ने भाग लिया और विभिन्न नेतृत्व कौशल सीखे।

   - प्रशिक्षण में आधुनिक वित्तीय प्रबंधन तकनीकों और डिजिटल बैंकिंग प्रणाली के महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया।
3. **संस्थाओं में पारदर्शिता और सदस्यों की जिम्मेदारी:**
   - उज्जैन नागरिक सहकारी पेढ़ी के उपाध्यक्ष सागर साहबजी ने कहा कि यदि संस्थाओं के पदाधिकारी और सदस्य ईमानदारी से कार्य करें, तो वित्तीय कठिनाइयों से बचा जा सकता है।
   - सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और समय पर ऋण चुकाने पर ध्यान देना चाहिए।
4. **आधुनिक तकनीक और सहकारी संस्थाओं का भविष्य:**
   - जिला सहकारी संघ उज्जैन के अध्यक्ष प्रभाकर सुपेकर ने कहा कि डिजिटल तकनीक और पारदर्शिता को बढ़ावा देना सहकारी संस्थाओं की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।
   - कार्यक्रम में डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय अनुशासन, एवं प्रशासनिक सुधार पर विशेष सत्र आयोजित किए गए।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ:

- 50 से अधिक सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।
- वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व विकास एवं डिजिटल बैंकिंग पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत सत्र आयोजित किए गए।
- केस स्टडी, समूह चर्चा एवं इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया।

समापन और निष्कर्ष

कार्यक्रम के अंतिम दिन जिला सहकारी संघ उज्जैन के प्रबंधक सुमेरसिंह सोलंकी ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण सहकारी संस्थाओं की प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय दक्षता को बढ़ाने में सहायक होगा।

इस दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम ने सहकारी संगठनों को नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह के प्रशिक्षण से सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता और दक्षता में सुधार होगा, जिससे उनके आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।

मध्यप्रदेश में 637 नवीन M-PACS के गठन की प्रक्रिया शुरू, वित्तीय सहायता की घोषणा

नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहयोग, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन रणनीति निर्धारित

भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (Apex Bank) ने प्रदेश में नवीन मल्टी-पर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज (M-PACS) के गठन की प्रक्रिया को गति देने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नाबार्ड (NABARD) द्वारा इस योजना के लिए वित्तीय सहायता एवं कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रथम चरण में 637 M-PACS की पहचान

नाबार्ड द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 637 नवीन M-PACS के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इन समितियों की पहचान सहकारिता विभाग द्वारा की गई है और इनके पंजीयन एवं संचालन हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। जिला सहकारी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला अधिकारियों के समन्वय से इस कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करें।

नवीन M-PACS को मिलने वाली वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत सरकार एवं नाबार्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं:

1. संस्थान सहायता एजेंसी (RSA) की नियुक्ति
   - प्रत्येक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (DCCB) को संस्थान सहायता एजेंसी (Resource Support Agency - RSA) के रूप में कार्य करना होगा।
   - अनुभवी व्यक्तियों को संसाधन व्यक्ति (Resource Person) के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
   - इन संसाधन व्यक्तियों को रु. 20,000 प्रति माह प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा।
2. क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहयोग
   - प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकर्ता को रु. 5,000 प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी।
3. बेस लाइन स्टडी एवं सोशल मोबिलाइजेशन
   - प्रत्येक PACS के लिए रु. 3,500 की राशि अनुमोदित की गई है।
4. बाय लॉ की तैयारी एवं पंजीयन खर्च
   - प्रत्येक PACS के लिए रु. 1,000 की सहायता प्रदान की जाएगी।
5. यात्रा, बैठक एवं व्यवसाय विकास योजना
   - प्रत्येक PACS को रु. 1,000 का अनुदान मिलेगा।
   - वित्तीय सहायता 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध

नाबार्ड ने स्पष्ट किया है कि यह वित्तीय सहायता 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद आवश्यकता अनुसार इस अवधि को बढ़ाए जाने की संभावना है।

जिला सहकारी बैंकों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी

Apex Bank ने सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में नवीन M-PACS के गठन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें। जिला अधिकारियों के सहयोग से इस योजना को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया है।

नवीन M-PACS से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के लागू होने से गांवों में वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, किसानों को ऋण एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं कृषि-आधारित व्यवसायों को नया प्रोत्साहन मिलेगा।

(पृष्ठ 1 का शेष)

किसानों को अब पांच रुपये में मिलेगा...

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह किसानों की सरकार है। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर आभार व्यक्त करने के लिए किसानों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खेती की व्यवस्था बेहतर करने, नवीन तकनीक अपनाने, शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करने का किसानों को संकल्प दिलाया।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि किसान भारतीय अर्थ व्यवस्था की बैकबोन हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में किसानों को मिल रही सुविधाओं से राज्य पुन: कृषि में देश में सिरमोर बनेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गेहूँ और धान के बारे में घोषणा कर किसानों की मेहनत को सम्मान दिया है। खजुराहो सांसद श्री वी.डी .शर्मा ने कहा कि किसान मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव आभार व्यक्त करने का निर्णय सराहनीय है। इस ऐतिहासिक फैसले से किसान परिवारों में प्रसन्नता का संचार हुआ। किसान मोर्चा के अध्यक्ष तथा सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा किसान हित में लिए गए निर्णयों के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से आभार माना।

मुख्यमंत्री निवास में किसान आभार सम्मेलन के अवसर पर ऊर्जा, उद्यानिकी, खाद्य नागरिक आपूर्ति, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई।

कार्यक्रम में खेल, युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, नगर निगम भोपाल अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

खेती में कीट नियंत्रण के लिये किसान कर रहे सोलर लाइट ट्रेप का उपयोग

भोपाल : बालाघाट जिले में धान की पैदावार काफी अच्छी होती है। किसानों को धान एवं अन्य फसलों में कीट नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सौर ऊर्जा आधारित सोलर लाइट ट्रेप उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के ग्राम कटंगझरी के किसान वीरेन्द्र धान्द्रे एवं अन्य किसान सफलतापूर्वक सोलर लाइट ट्रेप का उपयोग कर रहे हैं।

सोलर लाइट ट्रेप खेत में एक स्थान पर रखा जाता है। इस यंत्र में अल्ट्रावायलेट लाइट लगी रहती है। दिन में सूर्य के प्रकाश में पेनल द्वारा ऊर्जा एकत्रित होती है और अंधेरा होने पर सेंसर के कारण यंत्र में लाइट चालू हो जाती है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ट्रेप में कीटों के आने के बाद कीट नीचे लगी जाली में फँस जाते हैं। इस प्रकार खेत में किसानों को तना छेदक तितली और अन्य कीटों से फसलों को बचाने में मदद मिलती है। किसान बगैर कीटनाशक दवाओं के उपयोग से फसल को बचाने में सफल हो जाते हैं। किसान खेतों में इस यंत्र को बाँस के सहारे खड़ा करते हैं। एक कृषि यंत्र 3 से 5 एकड़ के लिये पर्याप्त होता है। दिन में सोलर पेनल द्वारा बेट्री चार्ज होती है। किसानों को यह यंत्र 2500 से 3500 हजार रूपये तक बाजार में उपलब्ध रहता है। किसानों को प्रति हेक्टेयर 500 रूपये अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

ड्रेगन फ्रूट की खेती कर किसानों के लिये मिसाल बने कटंगी के भूपेन्द्र

भोपाल :बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के ग्राम सीताखो के युवा किसान भूपेन्द्र शरणागत ड्रेगन फ्रूट की खेती कर अन्य किसानों के लिये मिसाल बन गये हैं। भूपेन्द्र वर्ष 2021 से ड्रेगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं।

43 वर्षीय भूपेन्द्र बताते हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में पढ़ाई की है। उनका परिवार लम्बे समय से खेत में धान, गेहूँ और चना की खेती करता आ रहा था। उन्होंने यह महसूस किया कि खेती की लागत से ज्यादा उन्हें लाभ नहीं हो रहा है। परिवार की सीमित आय को देखते हुए उन्होंने कुछ नया करने का विचार किया। उनके एक भाई नार्वे में रहते हैं। भाई की तरफ से उन्हें ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की सलाह मिली। फिर उन्होंने गोंदिया जिले के रायपुर स्थित किसान बालचन्द्र ठाकुर के फार्म जाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जानकारी ली।

भूपेन्द्र ने शुरूआत में 50 डिस्मिल खेत में ड्रेगन फ्रूट की खेती प्रारंभ की। उन्होंने बताया कि ड्रेगन फ्रूट की खेती के लिये खेत में एक निश्चित दूरी पर छोटे-छोटे बाँस के खंबे लगाये जाते हैं। इन खंभों पर अंगूर की खेती की तरह ही ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाये जाते हैं। एक खंमे पर 4 पौधे लगाये जाते हैं। ड्रेगन फ्रूट मूलत: अमेरिका का फल है और कैक्टस प्रजाति का पौधा है। एक बार इसका पौधा लगाने पर वह 25 सालों तक फसल देता है। किसान भूपेन्द्र बताते हैं कि ड्रेगन फ्रूट की खेती पर 10 लाख रूपये की लागत लगा चुके हैं। इस वर्ष उन्हें 50 डिस्मिल के खेत में 3 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट की पैदावार मिली है। यह फसल 200 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से आसानी से घर बैठे बिक जाती है। भूपेन्द्र का इरादा ड्रेगन फ्रूट की खेती को बढ़ा कर 2 एकड़ तक करने का है। इसमें एक हजार पौधे लगायेंगे जिससे प्रति एकड़ 7 टन ड्रेगन फ्रूट का उत्पादन मिलेगा। वे खेत में जैविक खाद का ही उपयोग कर रहे हैं। ड्रेगन फल एंटी आक्सीडेंट के साथ फेट रहित और उच्च फायबर युक्त होता है। इसके सेवन से पाचन तंत्र और ह्म्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। इस वजह से इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है।

कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न, प्रशिक्षुओं को मिली नई पहचान

उज्जैन, वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) के अंतर्गत गुरु-शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का 12 जनवरी 2025 को भार्गव नगर, उज्जैन में भव्य समापन हुआ। इस दो महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं और युवा कारीगरों को कढ़ाई कला में निपुण बनाया गया। कार्यक्रम का संचालन मास्टर ट्रेनर प्रीति साठे एवं सहायक मास्टर वैषाली साठे ने किया।

प्रशिक्षण के मुख्य आकर्षण

- पारंपरिक एवं आधुनिक कढ़ाई तकनीकों की गहन जानकारी
- डिज़ाइनिंग, धागों का चयन, फिनिशिंग वर्क और बाजार रणनीतियाँ
- स्वरोजगार के अवसरों पर विशेष सत्र
- प्रशिक्षण के दौरान तैयार किए गए कढ़ाई के सुंदर नमूने प्रदर्शित किए गए

प्रशिक्षुओं का उत्साह और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

कार्यक्रम के दौरान 30 से अधिक महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया और पारंपरिक कढ़ाई तकनीकों को सीखा। समापन समारोह में प्रतिभागियों ने अपने तैयार किए हुए कढ़ाई के परिधान और उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिन्हें अतिथियों और स्थानीय व्यापारियों से सराहना मिली।

प्रशिक्षण के बाद रोजगार और उद्यमिता के अवसर

यह प्रशिक्षण केवल एक कला सीखने का माध्यम नहीं था, बल्कि प्रतिभागियों को स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करने की दिशा में भी मार्गदर्शन दिया गया। कई प्रशिक्षुओं ने बुटीक, ऑनलाइन मार्केटिंग (Etsy, Amazon, Flipkart) और स्थानीय व्यापारियों से जुड़कर काम करने की योजना बनाई है।

समापन समारोह और प्रमाण-पत्र वितरण

समापन कार्यक्रम में विशेष अतिथियों, स्थानीय अधिकारियों और हस्तशिल्प विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मास्टर ट्रेनर प्रीति साठे ने अपने संबोधन में कहा, "यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कढ़ाई कला को सहेजने और इसे एक व्यावसायिक रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें गर्व है कि हमारे प्रशिक्षु अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं।"

भविष्य की योजनाएँ

इस सफल प्रशिक्षण के बाद, उज्जैन में और भी हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत हस्तशिल्पकारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने, बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाने और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।

यह कार्यक्रम स्थानीय कारीगरों को नई पहचान देने के साथ-साथ कढ़ाई कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य विवरण संबंधित जानकारी

घोषणा फार्म चार (नियम – 8)

1.	प्रकाशन स्थल	:	**मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई - 8 / 77 शाहपुरा, भोपाल**
2.	प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	:	**गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई - 8 / 77 शाहपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	:	**गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई - 8 / 77 शाहपुरा, भोपाल
5.	सम्पादक का नाम	:	**गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित गणेश प्रसाद मांझी
6.	क्या भारतीय नागरिक हैं	:	**हाँ**
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो।	:	यह समाचार पत्र मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं।

मैं गणेश प्रसाद मांझी एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

दिनांक 16 मार्च 2025

सही / -
(गणेश प्रसाद मांझी)
प्रकाशक

स्टोन कार्विंग प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न, कारीगरों को मिला नया आयाम

जबलपुर – भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) के अंतर्गत आयोजित गुरु-शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्टोन कार्विंग) ग्राम खुलरी, जिला जबलपुर (म.प्र.) में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था।

20 नवंबर 2024 से 19 जनवरी 2025 तक चले इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर श्री जागेश्वर साहू और सहायक मास्टर श्री अनुराग साहू ने प्रतिभागियों को पत्थरों की नक्काशी, आधुनिक औजारों के उपयोग, डिजाइनों की बारीकियों और बाजार में उत्पादों की मांग से परिचित कराया। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने कई सुंदर और कलात्मक कृतियां तैयार कीं, जो उनके हुनर और सीखने की लगन को दर्शाती हैं।

प्रतिभागियों की उपलब्धियां

कार्यक्रम के समापन अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षुओं द्वारा निर्मित स्टोन कार्विंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया। इन कलाकृतियों को स्थानीय लोगों और अतिथियों ने सराहा। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए, जिससे कारीगर आगे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को विकसित कर सकें।

विशेषज्ञों ने प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार, डिजिटल मार्केटिंग और सरकारी सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी, ताकि वे इस कला को केवल परंपरा तक सीमित न रखकर इसे रोजगार का जरिया बना सकें।

प्रशिक्षुओं की प्रतिक्रियाएँ

इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कारीगरों ने इसे अपनी कला को निखारने और व्यावसायिक रूप से विकसित करने का अनूठा अवसर बताया। एक प्रशिक्षु ने कहा,"इस प्रशिक्षण से हमें नई तकनीकों की जानकारी मिली और हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। अब हम अपने उत्पादों को ऑनलाइन और बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।"

संभावनाएँ और आगे की राह

इस सफल आयोजन के बाद आयोजकों ने इसे अन्य हस्तशिल्प समूहों तक विस्तारित करने की योजना बनाई है, ताकि पारंपरिक कलाओं को संरक्षण और बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, प्रशिक्षित कारीगरों को सरकारी योजनाओं और बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने और भारत की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को जीवंत रखने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

बटिक प्रिंट प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न - हस्तशिल्पकारों को मिला नया उत्कर्ष

इंदौर, वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) के अंतर्गत गुरु-शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बटिक प्रिंटिंग प्रशिक्षण 10 जनवरी 2025 को सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। मास्टर ट्रेनर मो. नासिर छीपा और सहायक मास्टर प्रभुदयाल के कुशल मार्गदर्शन में इस दो माह के प्रशिक्षण में 25 से अधिक शिल्पकारों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने मोम प्रतिरोध विधि, डिज़ाइन निर्माण, रंग संयोजन और फाइनल प्रोडक्ट की फिनिशिंग जैसी प्रमुख तकनीकों में दक्षता प्राप्त की। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल बटिक प्रिंटिंग की परंपरागत विधियों को सिखाना था, बल्कि इसे आधुनिक व्यापारिक अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना भी था।

प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और सरकार द्वारा इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। कई प्रशिक्षुओं ने अपने स्वयं के बटिक प्रिंट यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है, जबकि कुछ ने हस्तशिल्प मेलों और बाजारों में उत्पादों को बेचने की तैयारी कर ली है।

इस कार्यक्रम से जिन्दा खेड़ा सहित इंदौर क्षेत्र में हस्तशिल्प कला को नया प्रोत्साहन मिला है। बटिक प्रिंटिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार, विभिन्न संस्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जुड़ने के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और "वोकल फॉर लोकल" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और उन्हें भविष्य में बाजार से जुड़ने और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

भोपाल में जूट हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

भोपाल – परंपरागत हस्तशिल्प को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को इस कला में दक्ष बनाने के उद्देश्य से वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) के तहत गुरु-शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बुद्ध विहार, पंचशील नगर, भोपाल में 5 दिसंबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक सफलतापूर्वक चला। इस प्रशिक्षण का आयोजन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रयोजन एवं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के संयोजन में किया गया, जिसमें जूट हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और कारीगरों को तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

- अवधि: 5 दिसंबर 2024 से 4 फरवरी 2025
- स्थान:बुद्ध विहार, पंचशील नगर, भोपाल
- मास्टर ट्रेनर:मीना तिवारी
- सहायक मास्टर ट्रेनर:सुनीता यादव

प्रशिक्षण का उद्देश्य:

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जूट हस्तशिल्प को संरक्षित करते हुए नए कारीगरों को प्रशिक्षित करना, उन्नत तकनीकों से परिचित कराना और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना था। प्रतिभागियों को पारंपरिक कला में आधुनिक तकनीकों का समावेश करने की प्रेरणा दी गई।

प्रशिक्षण की प्रमुख झलकियाँ

1. जूट के कच्चे माल की पहचान एवं गुणवत्ता सुधार पर प्रशिक्षण।
2. जूट उत्पादों के निर्माण में पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का उपयोग।
3. डिज़ाइनिंग, बुनाई, और परिष्करण प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी।
4. सतत विकास और पर्यावरण हितैषी हस्तशिल्प तकनीकों पर जोर।
5. स्व-रोजगार और विपणन कौशल का प्रशिक्षण।
6. हस्तशिल्प उत्पादों की ब्रांडिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री रणनीतियाँ।
7. महिला कारीगरों को विशेष रूप से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय और विपणन परामर्श।
8. जूट उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं और आवश्यक प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण।

शिक्षा और नवाचार का संगम

इस प्रशिक्षण में जूट हस्तशिल्प की पारंपरिक विधियों को आधुनिक डिज़ाइन और मार्केटिंग रणनीतियों के साथ जोड़ा गया, जिससे कारीगरों को नई संभावनाएँ मिलीं। प्रशिक्षुओं ने विभिन्न जूट उत्पादों जैसे बैग, चटाई, होम डेकोर आइटम, और गिफ्ट आइटम बनाने की कला सीखी। साथ ही, उन्हें कस्टमाइज़्ड उत्पादों की मांग को पूरा करने की तकनीक भी सिखाई गई।

जूट हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार

भोपाल के सेमरा कला एवं चौकसे नगर में भी यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का आयोजन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रयोजन एवं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के संयोजन में किया गया।

- अवधि: 13 नवम्बर 2024 से 12 जनवरी 2025, 29 नवंबर 2024 से 28 जनवरी 2025 एवं 05 दिसम्बर 2024 से 04 फरवरी 2025।
- मास्टर ट्रेनर:राज्य पुरस्कार प्राप्त ट्रेनर नीतू यादव, हुमा खान।
- सहायक मास्टर ट्रेनर:संगीता यदुवंशी, रजिया अबरार।

प्रशिक्षण की उपलब्धियाँ

- 30 से अधिक प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया और जूट हस्तशिल्प की बारीकियों को सीखा।
- प्रशिक्षण के दौरान जूट से बैग, चटाई, टोकरी, गृह सज्जा सामग्री एवं अन्य उत्पादों का निर्माण किया गया।
- प्रतिभागियों को स्वरोजगार के नए अवसरों की जानकारी दी गई।
- महिला कारीगरों को आत्मनिर्भरता के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया।
- स्थानीय बाजारों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पाद विपणन की रणनीतियाँ सिखाई गई।
- समापन समारोह में सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

भविष्य की संभावनाएँ

समापन समारोह में उपस्थित अतिथियों ने प्रशिक्षुओं द्वारा बनाए गए जूट उत्पादों की सराहना की। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर नीतू यादव एवं हुमा खान ने कहा कि "इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से हस्तशिल्प कला को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।" सहायक मास्टर ट्रेनर संगीता यदुवंशी एवं रजिया अबरार ने कहा कि "प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कारीगरों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के अवसर उपलब्ध हैं, जिससे वे अपने हस्तशिल्प व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।"

विशेषज्ञों के विचार

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर उद्योग विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों ने जूट हस्तशिल्प की बढ़ती मांग और इसके उज्ज्वल भविष्य पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने कहा कि "भारत में जूट उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए, प्रशिक्षित कारीगरों को अपने उत्पादों को बड़े पैमाने पर विपणन करने की आवश्यकता है।" इसके साथ ही, स्थानीय हस्तशिल्प को वैश्विक मंच पर पहुँचाने के लिए सरकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ उठाने पर भी जोर दिया गया।

सरकार की भूमिका और आगे की योजनाएँ

भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित कर रही हैं। प्रशिक्षुओं को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिसमें उन्हें मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई।इस कार्यक्रम से स्थानीय कारीगरों को न केवल नई तकनीकों की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी मिले। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जूट हस्तशिल्प उद्योग को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। सरकार द्वारा हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी किया जाता रहेगा। इस पहल से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग भी नई ऊँचाइयों तक पहुँचेगा।

भोपाल में डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास कार्य-शाला एवं गुरु-शिष्य प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

भोपाल:मध्य प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को सहेजने और स्थानीय कारीगरों को नवीन तकनीकों से परिचित कराने के उद्देश्य से डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला एवं गुरु-शिष्य प्रशिक्षण कार्यक्रमका आयोजन किया गया। यह कार्यशाला भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय कीवृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS)के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के संयोजन में आयोजित की गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जरी जरदोजी कला को आधुनिक डिज़ाइनों एवं विपणन तकनीकों के साथ जोड़कर उसे नए बाज़ारों तक पहुँचाना था।

कार्यशाला का आयोजन

यह विशेष कार्यशाला गाँधी भवन, भोपाल एवं चौकसे नगर, जिला भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें हस्तशिल्प कारीगरों, प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों ने सहभागिता की।

- **अवधि:** 26 नवंबर 2024 से 25 जनवरी 2025 एवं 25.11.2024 से 24.01.2025, • **डिज़ाइनर:**अर्चना सिंह, • **मास्टर ट्रेनर:**फिरोज जहाँ एवं हुमा खान, • **सहायक मास्टर ट्रेनर:** रजिया अबरार

इस कार्यशाला में कारीगरों को जरी जरदोजी हस्तशिल्प के परंपरागत कौशल में नवीनता लाने के लिए डिज़ाइन और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही, उनके उत्पादों कीबाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु व्यावसायिक रणनीतियाँ भी सिखाई गई।

कार्यशाला के उद्देश्य एवं प्रशिक्षण की मुख्य झलकियाँ

इस कार्यशाला का उद्देश्य भोपाल के पारंपरिकजरी जरदोजी हस्तशिल्प क्लस्टर को नवाचार, डिज़ाइन, उत्पादन प्रक्रिया एवं विपणन रणनीतियों से सशक्त करना था। प्रशिक्षण सत्रों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को सम्मिलित किया गया—

1. पारंपरिक जरी जरदोजी तकनीकों का अध्ययन:कारीगरों को प्राचीन और परंपरागत कढ़ाई तकनीकों का विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।
2. आधुनिक डिज़ाइनों का समावेश:पारंपरिक कला को समकालीन डिज़ाइनों के साथ जोड़ने की तकनीकें सिखाई गई।
3. मशीन एवं हस्तनिर्मित तकनीकों का प्रशिक्षण:कारीगरों को मशीन से होने वाले कार्यों और हस्तनिर्मित प्रक्रियाओं की बारीकियाँ समझाई गई।
4. रंग संयोजन एवं एंब्रॉयडरी पैटर्न:आधुनिक एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए रंगों और कढ़ाई पैटर्न के समन्वय की ट्रेनिंग दी गई।
5. व्यावसायिक प्रशिक्षण:कारीगरों को उत्पादों कीब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग की रणनीतियाँ सिखाई गई, जिससे वे अपने उत्पादों को ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन मार्केट में प्रस्तुत कर सकें।
6. स्व-रोज़गार को बढ़ावा:आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए कारीगरों कोस्व-रोज़गार और स्टार्टअप की संभावनाओं पर मार्गदर्शन दिया गया।

कारीगरों को मिला नया मंच

भोपाल और आसपास के क्षेत्रों से आए हस्तशिल्प कारीगरों ने इस कार्यशाला में अपने पारंपरिक कौशल को आधुनिक तकनीकों से समृद्ध किया। इस प्रशिक्षण से वे अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में बेहतर अवसरों के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम हुए। इस कार्यशाला ने न केवल जरी जरदोजी हस्तशिल्प की नई संभावनाओं के द्वार खोले, बल्कि इससे जुड़े कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।